

2023

**प्रश्न:** 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा। कारण दीजिये।

(150 शब्द, 15 अंक)

**From being net food importer in the Sixties, India has emerged as a net food exporter to the world. Provide reasons.**

**उत्तर:** 1960 के दशक के बाद भारत को दीर्घकालिक भोजन की कमी के कारण अन्य देशों से आयात और खाद्य सहायता पर निर्भर रहने के लिये मजबूर होना पड़ा, इसके उपरांत भारत ने खाद्यान्न का उत्पादन एवं निर्यात करने की अपनी क्षमता में काफी प्रगति की है। WTO की व्यापार सांख्यिकी समीक्षा (2022) के अनुसार, भारत वैश्विक कृषि निर्यातकों की शीर्ष 10 रैंकिंग में शामिल था।

प्रमुख कारक	सरकारी नीतियाँ
→	न्यूनतम समर्थन मूल्य, e-NAM, सब्सिडीयुक्त इनपुट बेहतर खरीद प्रणाली से किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया।
→	<b>निजी क्षेत्र की भागीदारी</b> खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि में निजी भागीदारी से बेहतर पहुँच, बुनियादी ढाँचा का विकास, साथ ही ई-चौपाल, टाटा किसान केंद्र आदि को बढ़ावा मिलता है।
→	<b>वैश्विक मांग</b> लगातार बढ़ते वैश्विक बाजारों में अधिक वैश्विक मांग ने भी भारतीय कृषि की संभावनाओं को बढ़ावा दिया है।
→	<b>अनुसंधान और विकास</b> निवेश से बेहतर प्रौद्योगिकियों एवं तरीकों को अपनाने में सहायता मिली।
→	<b>व्यापारिक उदारीकरण</b> 1990 के दशक में तथा उसके उपरांत व्यापार के उदारीकरण ने भी बेहतर निर्यात में योगदान दिया।
→	<b>हरित क्रांति</b> 1960 के दशक में शुरू कृषि उत्पादन, बेहतर सिंचाई बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा।
→	<b>फसलों का विविधीकरण</b> सरकार का ध्यान भारत की खाद्य आपूर्ति में विविधता लाने पर है, जैसे- प्रौद्योगिकी मिशन आदि।

हालाँकि भारत ने शुद्ध खाद्य निर्यातक बनने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं जिनमें जलवायु परिवर्तन, सतत

कृषि, जल प्रबंधन शामिल हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि निर्यात का लाभ छोटे एवं सीमांत किसानों तक पहुँचे। इन चुनौतियों से निपटने से वैश्विक खाद्य बाजार में भारत की स्थिति और मजबूत होने के साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

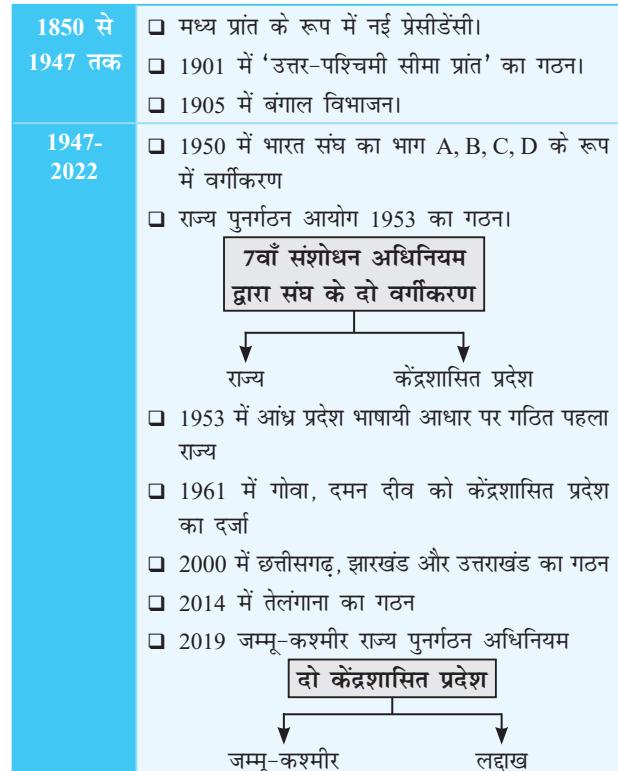
2022

**प्रश्न:** राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है। उदाहरण सहित विचार करें। (250 शब्द, 15 अंक)

**The political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous ongoing process since the mid-nineteenth century. Discuss with examples.**

**उत्तर:** विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों में परिवर्तन की प्रक्रिया राज्यों का पुनर्गठन कहलाती है, जिसकी शुरुआत अंग्रेजी शासन में नई प्रेसिडेंसियों के उदय से लेकर जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 तक साश्वत रूप में देखी जा सकती है। भारतीय सर्विधान का अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठन की अनुमति देता है।

राज्य पुनर्गठन के इस विकासक्रम को हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं—



उपरोक्त के अतिरिक्त भी वर्तमान में विदर्भ, बोडोलैंड जैसे राज्यों की मांग निरंतर की जा रही है। अतः यह कहा जा सकता है कि राज्यों का पुनर्गठन एक निरंतर प्रक्रिया है।

**प्रश्न:** भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों एवं सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

### Assess the main administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of Indian Princely States.

**उत्तर:** भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग 48% भाग पर 565 रियासतें कायम थीं, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत निम्न विकल्प दिये गए— वे भारत या पाकिस्तान में अपना विलय कर लें या स्वतंत्र रहने का निर्णय कर लें। इन्हीं प्रावधानों ने रियासतों के एकीकरण के मार्ग में समस्या उत्पन्न कर दी।

भारत में रियासतों के एकीकरण की निम्नलिखित प्रशासनिक व सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएँ थीं—

प्रशासनिक समस्याएँ	सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएँ
□ ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा ↓	□ हैदराबाद की अधिकांश जनता हिन्दू, किंतु शासक मुस्लिम-स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा।
□ इसे राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता के रूप में देखा	□ राजपूत रियासतों में हिन्दू बाहुल्य आबादी व हिन्दू राजा होने पर भी पाकिस्तान की ओर झुकाव
□ विलय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर	□ जूनागढ़ की अधिकांश जनता हिन्दू, किंतु राजा मुस्लिम → पाकिस्तान में विलय की इच्छा
□ प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के कारण रियासतें (कुछ) स्वतंत्र अस्तित्व का सपना देख रही थीं	□ कश्मीर की अधिकांश जनता मुस्लिम, किंतु शासक हिन्दू-स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा।
□ हैदराबाद के विरुद्ध तेलंगाना विद्रोह	

उपरोक्त समस्याओं के साथ भारतीय रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी सरदार वल्लभाई पटेल को दी गई, जिन्होंने रियासतों के समक्ष मुख्यतः दो प्रस्ताव रखे—

- यथास्थिति समझौता (स्टैंड स्टिल)
  - ◆ रियासतें रक्षा, संचार विदेश मामले भारत सरकार को दे दें।
- इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
  - ◆ भारत में रियासत का विलय कर रियासत के शासक को उस प्रदेश का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा।
  - ◆ शासकों के खर्चों के लिये “प्रिवी पर्स” की व्यवस्था।

यद्यपि अधिकांश रियासतों ने प्रिवी पर्स और पद ग्रहण किया, किंतु जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर रियासतों ने कठिन समस्याएँ खड़ी कर दी थीं। अंत में जूनागढ़ को जनमत संग्रह, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई (ऑपरेशन पोलो) और कश्मीर को विलय-पत्र द्वारा भारत में शामिल किया गया।

**प्रश्न:** चर्चा करें कि क्या हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिये लाभप्रद है या नहीं है?

(150 शब्द, 10 अंक)

**Discuss whether formation of new states in recent times is beneficial or not for the economy of India.**

**उत्तर:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को नए राज्यों के गठन, नामों या सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार है, जिसका प्रयोग करते हुए 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का भाषायी आधार पर गठन किया गया, जिसके पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों में नए राज्यों के गठन की मांग ने जोर पकड़ लिया और छत्तीसगढ़, झारखण्ड, तेलंगाना, उत्तराखण्ड जैसे राज्यों का निर्माण किया गया।

वर्तमान में भी बोडोलैंड, बुंदेलखण्ड व विदर्भ जैसे नए राज्यों के गठन की मांग की जा रही है, जबकि आलोचकों का मत है कि नए राज्यों के गठन से देश के संसाधनों का अपव्यय होगा और अर्थव्यवस्था को कई रूपों में प्रभावित करेगा—

#### नए राज्यों के गठन के लाभ

- सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास
- बेहतर आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है (उदाहरण— उत्तर प्रदेश)
- प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर दोहन (उदाहरण— छत्तीसगढ़, झारखण्ड)
- नृजातीय संघर्ष एवं क्षेत्रवाद की भावना में कमी
- योजनाओं की सही लाभार्थियों तक पहुँच (छत्तीसगढ़ का PDS मॉडल)
- शासन एवं प्रशासन का सुगम संचालन संभव (उदाहरण— हरियाणा)

उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त नए राज्यों के गठन की अपनी कुछ सीमाएँ भी हैं, जो निम्नलिखित हैं—

#### नए राज्यों के गठन की सीमाएँ

- विवाद समाधान तंत्रों पर अत्यधिक व्यय
- अलग-अलग प्रशासनिक भवन व कार्यालय की स्थापना
- नदी, जमीन जैसे संसाधनों पर विवाद
- संसाधनों के बँटवारे की समस्या
- अधिकांश नए राज्यों का गठन बोटबैंक की राजनीति से प्रभावित है
- नागरिकों के मध्य कटुता, द्वेष एवं हिंसा की भावना बढ़ने की आशंका

**2015**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नए राज्यों का गठन एक सिक्के के दोनों पहलू के समान है, जिसके अपने कुछ लाभ व हानियाँ हैं।

### आगे की राह

- सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा
- अबाध मांगों की जाँच के लिये स्पष्ट मानदंड होना चाहिये
- सत्ता का संकेंद्रण, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता आदि का समाधान
- वोट बैंक की राजनीति के विपरीत आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता को प्रधानता दी जानी चाहिये

**2016**

प्रश्न: क्या भाषायी राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है? (200 शब्द, 12½ अंक)

**Has the formation of linguistic States strengthened the cause of Indian Unity?**

**उत्तर:** आजादी के बाद भारत में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की तीव्र मांग को देखते हुए सरकार ने 'एस.के. धर आयोग' तथा 'जे.वी.पी. समिति' का गठन किया। इन समितियों ने भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हुए व्यापक आंदोलनों के कारण 1953 में पहले भाषायी राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया।

इसके पश्चात् राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषायी आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्रशासित प्रदेशों का गठन किया गया, जिससे निम्नलिखित रूप में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिला।

### भारतीय एकता को बढ़ाने वाले तत्त्व

- संपूर्ण भारतीयों के बीच संचार की सुविधा
- क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया
- क्षेत्रीय भाषा को भी महत्व दिया जा सका
- संघीय ढाँचे को प्रभावित किये बिना केंद्र एवं राज्य के संबंध पूर्ववत् बने रहे
- मातृभाषा में सरकार से संपर्क स्थापित करने तथा प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करने में सहूलियत प्रदान की
- त्रिभाषा सिद्धांत ने हिन्दी व अंग्रेजी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
- आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका
- जनता की भावनाओं का मान रखा गया

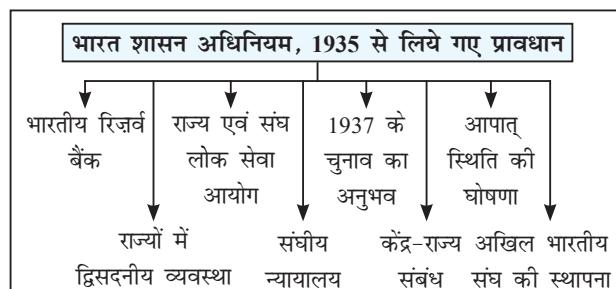
वर्तमान में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कमज़ोर पड़ती गई तथा उसका स्थान प्रशासनिक शिथिलता एवं आर्थिक विषमता ने ले लिया, जिसके तहत झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड तथा तेलंगाना जैसे राज्यों का गठन किया गया, किंतु अभी भी विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवाद तथा नदी जल बँटवारे जैसे प्रश्न अनसुलझे हुए हैं।

**प्रश्न:** स्वतंत्र भारत के लिये संविधान का मसौदा केवल तीन साल में तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करना संविधान सभा के लिये कठिन होता, यदि उनके पास भारत सरकार अधिनियम, 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होता। चर्चा कीजिये। (200 शब्द, 12½ अंक)

**It would have been difficult for the Constituent Assembly to complete its historic task of drafting the Constitution for Independent India in just three years but for the experience gained with the Government of India Act, 1935. Discuss.**

**उत्तर:** भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसका निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा के 300 से अधिक सदस्यों के अथक् प्रयासों द्वारा किया गया। संविधान निर्माण में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे कई विदेशी स्रोतों के साथ अनेक देशी स्रोतों का भी सहारा लिया गया, किंतु संविधान को आधार प्रदान करने में भारत शासन अधिनियम, 1935 की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

भारत शासन अधिनियम, 1935 निम्नलिखित रूप में भारतीय संविधान को आधार प्रदान करता है—



अतः यह कहा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम, 1935 ने निश्चित ही भारतीय संविधान निर्माताओं को एक ठोस आधार प्रदान किया, जिससे इतने कम समय में एक बेहतर संविधान बनकर तैयार हुआ, किंतु फिर भी इसके लिये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श तथा संविधान सभा के सदस्यों के अथक् प्रयास को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

**2013**

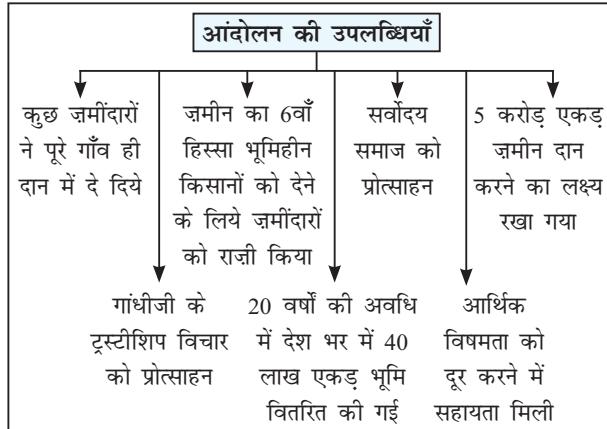
**प्रश्न:** आचार्य विनोबा भावे के भूदान व ग्रामदान आंदोलनों के उद्देश्यों की समालोचनात्मक विवेचना कीजिये और उनकी सफलता का आकलन कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)

**Critically discuss the objectives of Bhoodan and Gramdan movements initiated by Acharya Vinoba Bhave and their success.**

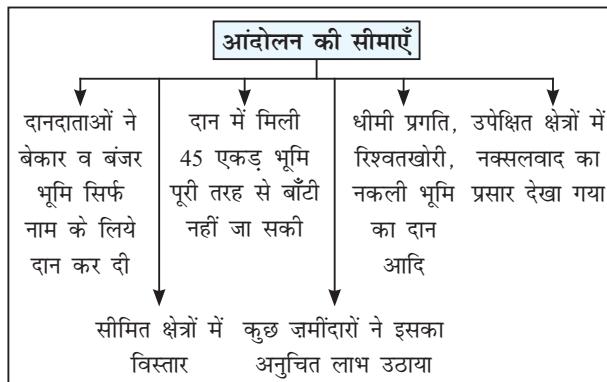
**उत्तर:** स्वतंत्रता पश्चात् कृषि जोत में व्याप्त असमानता, इससे उत्पन्न आर्थिक विषमता तथा भूमिहीन की दयनीय दशा को सुधारने हेतु विनोबा भावे द्वारा 1951 ई. में तेलंगाना के पोचमपल्ली गाँव से भूदान

आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का अगला चरण ग्रामदान आंदोलन था, जिसकी शुरुआत ओडिशा से हुई थी। इसका उद्देश्य जमींदारों व पट्टाधारकों को उनके भूमि अधिकारों को त्यागने के लिये राजी करना था।

इन आंदोलनों की उपलब्धियों को निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं—



उपरोक्त उपलब्धियों के बावजूद भी आंदोलन की सीमाएँ रहीं, जो निम्नलिखित हैं—



**अंततः** यह कहा जा सकता है कि यह आंदोलन अपने उद्देश्यों में अपेक्षित सफलताएँ प्राप्त नहीं कर सका, किंतु भविष्य में होने वाले भू-आंदोलनों के लिये इसने एक आधार प्रदान किया। चौंक, इन आंदोलनों के माध्यम से भूमि सुधार की रचनात्मक कोशिश की गई, जिस कारण इन आंदोलनों को 'रक्तहीन क्रांति' भी कहा गया।

**प्रश्न:** 'जय जवान जय किसान' नारे के उद्भव और महत्ता पर एक समालोचनात्मक लेख लिखिये। (200 शब्द, 10 अंक)

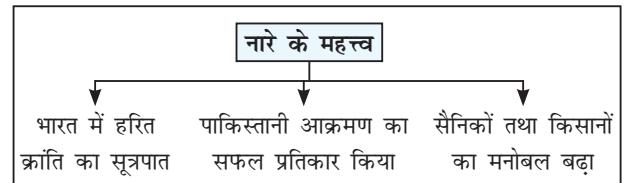
**Write a critical note on the evolution and significance of the slogan "Jai Jawan Jai Kisan".**

**उत्तर:** 'जय जवान जय किसान' का नारा सन् 1965 ई. में भारत-पाक युद्ध के समय तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था, जिसके मुख्यतः दो पक्ष थे— 'जवान' व 'किसान'। यह नारा सैन्य सुरक्षा एवं खाद्य सुरक्षा के बीच आंतरिक संबंधों को रेखांकित करता है। इसके साथ ही यह नारा इस ओर भी संकेत करता है कि सैन्य शक्ति एवं खाद्यान के मामले में आत्मनिर्भरत आवश्यक है।

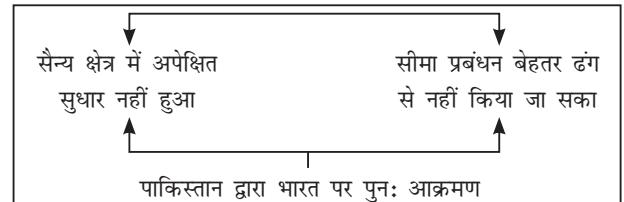
इस नारे के उद्भव में पीछे निम्नलिखित कारण थे—

- चीनी आक्रमण व युद्ध के पराजय के कारण भारतीय सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ था।
- देश में उस समय सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्मात्रा का अभाव था।
- 1965 में कई राज्य गंभीर सूखे की चपेट में आ गए थे।
- इसी समय पाकिस्तान ने भी अनुकूल समय जानकर भारत पर आक्रमण कर दिया।
- भारत-पाक युद्ध के दौरान अमेरिका को पीएल-480 स्क्रीम के तहत गेहूँ मिलने में समस्या।

यह नारा अपने आप में एक नारा ही मात्र नहीं था, अपितु इसके निम्नलिखित महत्त्व थे—



हालाँकि, यह नारा अपेक्षित प्रभाव नहीं दे सका, जिसे हम निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं—



**अंततः** यह कहा जा सकता है कि 'जय जवान जय किसान' का नारा तत्कालीन विषम परिस्थितियों में जवानों व किसानों में उत्साह भरने में किसी वैदिक अथवा तात्त्विक मंत्र से कम प्रभावशाली नहीं था, जिसने भारत को एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी।

**प्रश्न:** उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिये, जिनके कारण वर्ष 1966 में ताश्कंद समझौता हुआ। समझौते की विशिष्टताओं की विवेचना कीजिये। (200 शब्द, 10 अंक)

**Analyze the circumstances that led to Tashkent Agreement in 1966. Discuss the highlights of the agreement.**

**उत्तर:** ताश्कंद समझौता सोवियत संघ की मध्यस्थता में भारत के प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खाँ के बीच 11 जनवरी, 1966 को किया गया था। इस समझौते के अनुसार तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने आपसी मतभेद को भविष्य में शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे।

इस समझौते के लिये ज़िम्मेदार परिस्थितियों के विकास क्रम को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है—

- 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण।
- अमेरिका व चीन पाकिस्तान की तरफ से आए और सोवियत संघ भारत की तरफ से आया।

- सोवियत संघ, अमेरिका व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने दोनों देशों पर युद्ध विराम का दबाव डाला।
- सोवियत संघ की मध्यस्थता में ताशकंद में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ।  
इस समझौते के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित थे—
- भारत व पाकिस्तान अपनी सेनाओं को युद्धपूर्व की सीमा-रेखा तक पीछे हटा लेंगे एवं संघर्ष विराम का पालन करेंगे।
- इन देशों के बीच संबंध आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित होंगे।
- आपसी विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से, बलपूर्वक नहीं।
- दोनों देश ऐसी किसी भी दुर्भावना का प्रचार नहीं करेंगे, जिससे मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित होंगे।
- 1961 को वियना अभिसमय का पालन तथा राजनियिक संबंधों को बहाल किया जाएगा।

उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में शास्त्री जी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् व सोवियत संघ के दबाव में हाजीपीर दर्द से भी पीछे हटना पड़ा। जहाँ से अक्सर पाकिस्तानी घुसपैठिये कश्मीर में घुसपैठ कर सकते थे।

यद्यपि भारत ताशकंद समझौते के प्रति प्रतिबद्ध रहा, किंतु पाकिस्तान ने 1971, 1999 व उरी हमले से इस समझौते का उल्लंघन किया।

**प्रश्न:** उन परिस्थितियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये, जिनके कारण भारत को बांग्लादेश के उदय में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करना पड़ा। (200 शब्द, 10 अंक)

**Critically examine the compulsions which prompted India to play a decisive role in the emergence of Bangladesh.**

**उत्तर:** 1970 में पाकिस्तान के आम चुनाव में शेख मुजीबुर्रहमान (पूर्वी पाकिस्तान) की जीत हुई, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान के सेना व नेताओं ने स्वीकार नहीं किया और एक बड़ा राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। इस संकट का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, जिसके फलस्वरूप भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध हुआ और बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के रूप में विश्व के मानवित्र पर उभरा।

बांग्लादेश के उदय में भारत द्वारा निर्णायक भूमिका निभाने के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं को देख सकते हैं—

#### कारण

- पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की स्थिति के कारण भारत आए शरणार्थियों की समस्या के हल हेतु पाकिस्तान पर कार्रवाई का अत्यधिक दबाव
- अमेरिका एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पाकिस्तान से सहानुभूति
- भारत ने 'मुक्ति वाहिनी' नामक छापामार संगठन को सहयोग देना प्रारंभ कर दिया
- 3 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी भारत के कई सैन्य अड्डों पर हवाई हमला किया
- भारतीय सेना द्वारा जवाबी कार्रवाई कर उन्हें पराजित किया गया और पाकिस्तान के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया

अंततः 16 दिसंबर, 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश के रूप में एक पृथक् एवं स्वतंत्र राज्य उभरा।

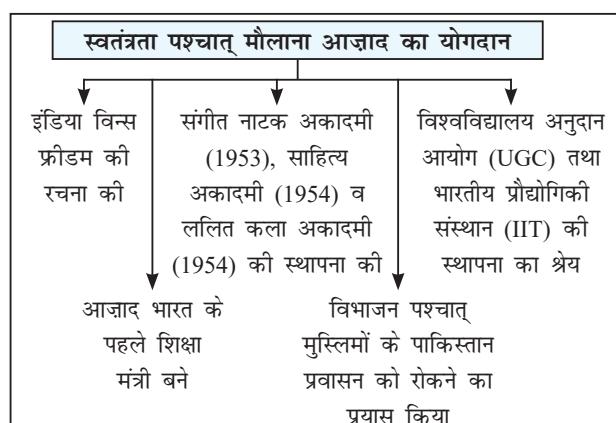
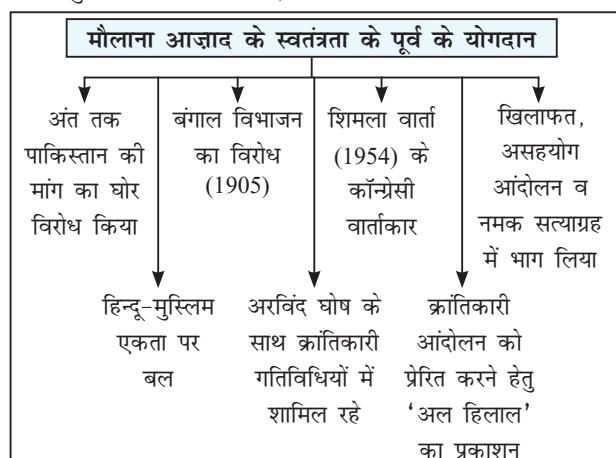
**प्रश्न:** स्वतंत्रता-पूर्व व स्वतंत्रता उपरांत भारत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदानों की विवेचना कीजिये।

(200 शब्द, 10 अंक)

**Discuss the contribution of Maulana Abul Kalam Azad to pre-and post-independent India.**

**उत्तर:** सऊदी अरब में 1888 में जन्मे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रखर राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार एवं लेखक थे। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, अपितु स्वतंत्रता पश्चात् भी देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।

● मौलाना आज़ाद के देश को दिये गए योगदानों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।



उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक एवं स्वतंत्रता पश्चात् शिक्षा व सांस्कृतिक विवादों में मौलाना आज़ाद का अमूलपूर्व योगदान है, जिस कारण उन्हें मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।